Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

भारत–नेपाल सीमा–विवाद में चीनी हस्तक्षेप का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव

डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय
सह–आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग, का.सु. साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या,उत्तर प्रदेश,
राधा जायसवाल
अनुसंधित्सु, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग, का.सु. साकेत पी0जी0 कालेज अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 4
Page Number : 52-55

Publication Issue :
July-August-2021

Article History
Accepted : 03 July 2021
Published : 10 July 2021

सांराश :– 17 वीं शताब्दी में जब नेपाल में गोरखों का शासन था। पृथ्वी नारायण शाह वहां के नरेश थे। तब भारत–नेपाल सीमा का निर्धारण किया गया । उस समय पृथ्वी नारायण ने नेपाल की सीमा को पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में सिक्किम तक बढ़ा लिया। ब्रिटिश और गोरखों का तराई इलाके में युद्ध हुआ और परस्पर बढ़ते विरोध के कारण सन् 1815 में सुगोली समझौता हुआ जिसमें पुनः मार्च 1816 में कुछ संशोधन किया गया। इस युद्ध में नेपाल को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। संधि के पश्चात् सन् 1858 में ब्रिटिश सरकार ने तराई के कुछ हिस्सों को नेपाल को वापिस कर दिया गया। तब से भारत व नेपाल के बीच के एक स्थायी सीमा बन गई। पिछले कुछ दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों पर काफी चर्चा हुई है। चर्चा का केन्द्रीय बिन्दु रहा दोनों देशों के बीच का पुराना सीमा विवाद और इस विवाद में नेपाल की स्थिति को लेकर वहां की सरकार का अचानक आक्रमक हो जाना। कुछ जानकार लोगों का मानना है कि नेपाल के इस आक्रमक रूख के पीछे चीन का हाथ है और ऐसा करने के लिए चीन ने नेपाल को उकसाया होगा। यहां तक भारत के सेना प्रमुख जनरल एम. एस. नरवणे ने भी कह दिया था कि लिपुलेख दर्रे के पास भारत द्वारा सड़क बनाने का विरोध नेपाल "किसी और देश के निर्देशों"पर कर रहा है।

मुख्य शब्द – नेपाल, भारत, चीन, सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेख, हस्ताक्षेप।

परिचय :– नेपाल की सीमा पांच भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम से मिलती है। भारत में लगभग 1 करोड़ नेपाली है। प्रत्येक साल एक लाख नेपाली भारत में प्रवेश करते है और कुछ प्रतिशत ही वापस जाते है। नेपाली लोगों की बड़ी संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। भारत–नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के सीमावर्ती निवासियों के लिए लाभदायक है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत नेपाल खुली सीमा काफी लाभप्रद है। क्योंकि हजारों नेपाली, तराई क्षेत्र में भारत के विभिन्न भागों में शिक्षा के लिए आते है। भारत में सीमा के पास स्वास्थ्य संस्थायें नेपाल सीमावर्ती निवासियों की बड़ी संख्या को आकर्षित करती है। अन्य नेपालियों को भारत में समान शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत को प्राकृतिक सुरक्षा दिए हुए है। यह सभी के सामने स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच नेपाल के होने के कारण ही आकस्मिक मुठभेड़ और संघर्ष की सैकड़ों आशंकाए टल जाती है। ऐसी सुरक्षा अरबों रूप्ए खर्च करके और सीमा सुरक्षा सेना रखकर भी पाना सम्भव नहीं है।

भारत नेपाल सीमा विवाद का इतिहास :– भारत नेपाल की सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। 1990 में नेपाल इस मुद्दे पर अनौपचारिक रूप से बाते करता था। अब उसने इस एजेंडें को औपचारिक रूप से उठाना शुरू कर दिया है। अगर हम इतिहास में जाए तो यह नेपाल और भारत ही है जो अभी भी बार्डर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। नेपाल–भारत सीमा मुद्दे पर भारत की और से तो शायद ही कभी आवाज आई हो, लेकिन नेपाल जो

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सन् 1990 से पहले इस मुद्दे को अनौपचारिक रूप से उठाता था। अब उसने इस ऐजेंडे को औपचारिक रूप से टेबल पर लाना शुरू कर दिया है।

सन् 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री आई. के. गुजराल की नेपाल यात्रा पर अधिकारिक रूप से सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। विदेश मंत्री जसवंत सिंह जब 1999 में कठमांडू आए तब फिर से इस पर चर्चा हुई। बाद में इस मुद्दे को दोनों देशों के उच्चस्तरीय संवाद जैसे कई मौकों पर बातचीत की सूची में रख गया। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों में इसका उल्लेख भी है। सबसे पहले यह मुद्दा 23 मार्च 2002 को भारत नेपाल संयुक्त बयान के 27वें पॉइंट में कवर किया गया । यह संयुक्त बयान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की भारत की अधिकारिक यात्रा के बाद जारी किया गया था। इस दस्तावेज में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और नेपाल के बीच वैज्ञानिक तरीकों से अंतरराष्ट्रीय सीमा को सीमांकित करने को बेहद जरूरी बताया था। इसके साथ ही जॉइंट टेक्निकल लेबल बार्डर कमिटी को यह काम 2003 तक पूरा करने का निर्देश दिया था। यह संयुक्त बयान ही था। जिसमें कालापानी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि "इस इलाके को लेकर दोनों पक्षों की धारणाएं " अलग अलग है।

इसी तरह, 24 से 26 नवम्बर 2008 में जब भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी नेपाल दौरे पर थे, तब जारी हुए संयुक्त बयान 13वें पॉइंट में लिखा गया था कि दोनों मंत्रियों ने नोट किया है कि टेक्निकल कमिटी ने भारत–नेपाल सीमा की 98 प्रतिशत वैज्ञानिक स्ट्रिप मैपिंग पूरी कर ली है और आगे कुछ इलाकों में सहमति के साथ मैपिंग पर हस्ताक्षर के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएगें।

इसके अलावा 4 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेपाल की अधिकारिक यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान के 12वें पॉइंट में लिखा गया था। कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने नेपाल–भारत के लंबित पड़े सीमा मुद्दों को जल्द सुलझानें की जरूरत बताई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से पहले ही इस अयोग ने विदेश सचिव को इस मुद्दे पर काम करने के निर्देश दिये थे। इसीलिए इस संयुक्त बयान में लिखा गया था कि दोनों प्रधानमंत्री लंबित पड़े सीमा विवाद (जिनमें कालापानी और सुस्ता शामिल है) को सुलझाने के लिए संयुक्त अयोग द्वारा विदेश सचिवों को निर्देशित करने का स्वागत करते है।

भारतीय पक्ष ने सीमा के लगभग 98 प्रतिशत सहमत हो चुके हिस्से पर जल्द हस्ताक्षर करने का जोर दिया। नेपाली पक्ष ने सभी बाकी मुद्दों को भी हल करने की इच्छा व्यक्त की है।

सीमा विवादित इलाके :– भारत–नेपाल के बीच सीमा विवाद की वजह कालीपानी, लिपुलेख व लिंपियाधुरा है। नेपाल के विवादित नक्शा जारी करने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव स्थिति की बनी हुई है। भारत की और से नवंबर 2019 में नया नक्शा प्रकाशित करने के करीब 6 महीने बाद मई में नेपाल ने अपने देश का नया संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा जारी किया था। जिसमें नेपाल ने उत्तराखंड के तीन क्षेत्रों पर अपना दावा जताने वाले इस नक्शे को नेपाल की संसद ने मंजूर कर दिया था।

कालापानी विवादः– कालापानी विवाद वैसे तो काफी पुराना है लेकिन इसकी ताजा शुरूआत जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद भारत सरकार के नये नक्शे को जारी करने से हुई। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किये गये राजनीतिक मानचित्र में कालापानी इलाके को भारतीय सीमाओं के अंदर दिखाया गया है। इस नये नक्शें पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के विदेश मंत्रायल द्वारा जारी एक बयान में कहा नेपाल सरकार दृढता से यह मानती है कि कालापानी नेपाल का हिस्सा है। नेपाल भारत सीमा पर कोई भी एक तरफा कार्यवाही नेपाल सरकार के लिए अस्वीकार्य होगी।

भारत–चीन–नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित कालापानी इलाका सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार का दावा है कि वर्ष 1816 में उसके और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौंली संधि के मुताबिक कालापानी उसका इलाका है। हालांकि इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नेपाल काली (अब महाकाली) नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा। 1860 के दशक में पहली बार इस इलाके में जमीन का सर्वे हुआ था। 1929 में कालापानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी।

लिपुलेख विवाद :– भारत ने लिपुलेख तक 80 किमी. लम्बा एक सड़क मार्ग तैयार किया था। जिसका रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियों द्वारा उद्घाटन किया था। ये सड़क चीन सीमा तक आखिरी भारतीय चौकी तक पहुंचती है लेकिन इस सड़क परियोजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि नेपाल का कहना है कि ये उसका इलाका है जिस पर भारत अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल में यह मामला इस कदर गर्म है कि ना केवल इसे संसद में उठाया गया बल्कि

काठमांडू में भारतीय दूतावास के समाने इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन भी हुआ। ये सड़क उत्तराखंड राज्य घटियाबागढ़ को हिमालय क्षेत्र में स्थित लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है।

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को 80 किमी. की यह सड़क बनने के बाद लम्बे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी और गाड़िया चीन की सीमा तक जा सकेंगी। धारचुला–लिपुलेख रोड,पिथौरागढ,तवाघाट, घटियाबागढ़ रूट का विस्तार है। ये सड़क घटियाबागढ़ से शुरू होकर लिपुलेख दर्रे पर खत्म होती है जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है।

नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। इस दावे के पक्ष में नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला भी दिया है। नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का इलाका जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी, और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का क्षेत्र है। इतना ही नहीं लिपुलेख दर्रे से लगे और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कालापानी के इलाके पर नेपाल अपना दावा करता है। हालाकि साल 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी में भारतीय सैनिक तैनात है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक अधिकारिक बयान जारी कर कहा " भारत की ये एक तरफा कार्यवाही "दोनों देशो के बीच सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर बनी सहमति के खिलाफ़ है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री इसी सड़क से जाते है। भारत ने ये जो सड़क तैयार किया था उसके दो उद्देश्य थे। पहला कैलाश मानसरोवर यात्रा का सुगम करना और दूसरा चीन सीमा पर स्थित भारत की आखिरी चौकी पर जल्दी पहुचना। पहले जब ये सड़क नहीं थी, तब इस सड़क पर पहुचाने में तीन दिन लगते थे, अब इस 80 किलो मीटर के मार्ग को बनने के बाद केवल तीन चार घण्टे ही लगेगें। प्राचीनकाल में तो इसका बहुत महत्व था क्योंकि भारत तिब्बत के बीच आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मानसून की भी संकलन तथा ठंडा में बर्फ से ढका होने के कारण इस तरह से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

उत्तराखण्ड से लगी चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे से 1991 में भारत–चीन व्यापार शुरू किया गया था। गौरतलब है कि भारत–चीन के बीच अपनी तरह का यह एक मात्र जमीनी व्यापार मार्ग है हालांकि दो साल पहले नाथुला दर्रे को भी खोल दिया गया था। लेकिन वहां से नाम मात्र का ही व्यापार होता था।

भारत की सुरक्षा चिंताः– भारत नेपाल संबंधो में मतभेद हाल के वर्षों मे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जब 2015 में नेपाल के संविधान मंसौदे को लेकर मधेसियों ने आन्दोलन किया था, तब भारत– नेपाल सीमा कई दिनों तक ठप रही थी। नतीजतन, नेपाल ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। लिहाजा, कुछ महीनों तक दोनों देशो के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इसके बाद फरवरी 2016 में नेपाल प्रधानमंत्री के0पी0 शर्मा ओली ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ बेहतर सम्बन्धों की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौर में भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद नौ समझौतो पर हस्ताक्षर किऐ गए और ऐसा लगा कि शायद दोनों देशों के बीच तनाव का दौर खत्म हो गया। लेकिन तभी नेपाल और चीन दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगे फिर नेपाल में राजनीतिक उठा–पटक के बाद सत्ता बदली और आखिरकार के0पी0 शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गये और इसी वर्ष जून में ओली जब चीन गये तक दोनों देशों के बीच 14 मुद्दो पर समझौते हुए। व्यापार को बढावा देने के लिए चीन–तिब्बत, रेल लिंक समझौता सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा देखा जाए तो, चीन भारी निवेश कर नेपाल में बुनयादी ढ़ांचा, मसलन–सड़क, बिजली आदि परियोजनाओं पर पहले ये ही काम कर रहा है। हाल ही में नेपाल को कई चीनी बंदरगाहों को उपयोग करने की भी अनुमति मिल गई है। यहीं कारण है कि नेपाल में चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और भारत का प्रभाव कम होता दिख रहा है। लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल सरकार के महत्वकांक्षा ही भारत–नेपाल रिश्ते में खटास ही मुख्य वजह है।

निष्कर्ष :– नेपाल द्वारा बार–बार भारत की उपेक्षा करने के पीछे कई कारक काम कर रहा है। नेपाल में चीन का बढ़ता हस्ताक्षेप नेपाल की आन्तरिक राजनीति और भारत की पडोस नीति की समस्या कुछ ऐसे पहलु है, जो दोनों देशो में मतभेद के कारण बन रहा है। जहां तक चीन का सवाल है तो उसने पिछले कुछ समय में नेपाल, श्रीलंका, बंगालादेश और मालदीप में अपनी सक्रियता बढाई है। वहां पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों को आर्थिक सहायता का लालच देकर

अपने प्रभाव में लाना चहता है। नेपाल में चीन द्वारा भारी निवेश इसी का दूसरा पहलु है अगर नेपाल के आंतरिक राजनीतिक की बात करे तो वहां पिछले 10 सालों में 10 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जहीर है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता उसकी विदेश नीति को संभलने नहीं दे रही है। वहां एक सशक्त और मजबूत नेता की सख्त जरूरत है। जो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध अस्थपित कर सके। भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत है भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूर–दरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह नेपाल में चीन का प्रभाव पड़ रहा है उसे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीन निवेश के सामने भारत की चमक फिकी पड रही है। लिहाजा भारत को कुटनीतिक सुझबुझ का परिचय देना होगा। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को बिगड़ रहा है और चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। लिहाजा भारत को चाहिए रकसौल कठमाडू रेल लिंक परियोजना को तय समय में पूरा करने की तत्परता दिखायें क्योंकि विकास परियोजना के माध्यम से चीन भारत पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच अस्थापित कर भारत की समप्रभुता को चुनौती देना का कोई भी कसर नहीं छोड़ता मेरा मान है कि भारत को गंभीर प्रयासों के जरिये नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों को साधने की जरूरत है। ताकि चीन जो पड़ोसी देशों में घुसकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने की कोशिश करता है उसे नाकाम किया जा सके।

संदर्भः–

1. श्रेष्या, हिरण लाल (नवम्बर 2000), नेपाल–इण्डिया रिलेशंस : सिक्युरिटी इशु, इंस्टीच्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स आइएफए, काठमांडू, नेपाल।
2. चतुर्वेदी, एस0के0 (1983) भारत–नेपाल संबंध, डी0के0 पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव डॉ0 एन0के0 (1983), भारत की विदेश नीति साहित्य भवन, आगरा।
4. वी0एल0फाडिया, " अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2009।
5. डॉ0 मुकेश देवी, (2017), नेपाल चीन के सम्बन्धः भारत की सुरक्षा चिंता, ब्लू रोज पब्लिशर्स।
6. प्रतियोगता दर्पण।
7. दृष्टि कन्टेट – अफेयर्स टूडे।
8. इंटरनेट
9. न्यूज पेपर
10. बी.बी.सी न्यूज।